माननीय न्यायमूर्ति के. पी. भंडारी और अमरजीत चौधरी के समक्ष,

एम. एल. पुरी, अधिवक्ता -याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, इसके पंजीकरण और अन्य के माध्यम से -उत्तरदाता

1993 की सिविल रिट याचिका सं **2019**

24 मार्च, **1993**

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226/227-उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्त) अधिनियम, 1954-धारा 22ख-लोकहित वाद-उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निपटान में रखी गई स्टाफ कारें जो अतिरिक्त मानक की नहीं हैं-पुरानी कारें बदली जाएंगी।

अभिनिर्धारित किया गया है कि हमारा विचार है कि उत्तरदाता न्यायाधीशों को स्टाफ कार प्रदान करने के लिए बाध्य हैं और कार के 80,000 किलोमीटर या पाँच साल पुरानी होने के बाद उन्हें बदला जाना चाहिए। गाड़ियों की मरम्मत के लिए काफी खर्च करना पड़ता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निपटान में रखी गई उन गाड़ियों के प्रतिस्थापन में विलम्ब करने का कोई औचित्य नहीं है जो पहले ही 80,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी हैं या पाँच वर्ष से अधिक पुरानी हैं।

(पैरा 17)

अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका की अनुमति दी गई है और प्रत्यर्थी को तुरंत सात कारों को खरीदने और बदलने का निर्देश देते हुए एक आदेश पत्र जारी किया गया है। हम आगे निर्देश देते हैं कि उत्तरदाता उन कारों को बदल देंगे जो पहले ही 80,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी हैं, या पाँच वर्ष से अधिक आयु के हैं, जो भी पहले हो, बिना किसी और देरी के।

(पैरा 19)

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

आर. एल. शर्मा, डी.ए.जी.हरियाणा, प्रतिवादी के लिए।

ए. के. भारद्वाज, उप सचिव (गृह) उत्तरदाता नं. 3. के लिए

कोई नहीं, प्रत्यर्थी नं. 2 के लिये

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति के. पी. भंडारी

(1) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री एम. एल. पुरी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में वर्तमान याचिका दायर की है। उन्होंने रिट याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 22-बी के अनुसार स्टाफ कार के हकदार हैं, जैसा कि संशोधित किया गया है (संक्षेप में 'अधिनियम') उन्होंने रिट याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निपटान में रखी गई कर्मचारियों की कारें पुरानी हैं और भरोसेमंद नहीं हैं। गाड़ियों को बदलने की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता का रुख यह है कि न्यायिक कार्यों के निर्वहन में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पंजाब और हरियाणा राज्यों के भीतर दूर-दराज के स्थानों की यात्रा करने की आवश्यकता होती है। वे लोक अदालतों की अध्यक्षता करने के लिए राज्य मुख्यालय भी जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निपटान में रखी गई कर्मचारियों की कारें पर्याप्त मानक की नहीं हैं। कभी-कभी कारें सड़क पर फंसी रहती हैं। उन्होंने आगे कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निपटान में रखी गई कारें उसी मानक की होनी चाहिए जो राज्य के मंत्रियों के निपटान में रखी जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकांश न्यायाधीशों के निपटान में रखी गई कारों को बदलने की आवश्यकता है। रिट याचिका में याचिकाकर्ता का यह भी रुख है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।

(2) रिट याचिका का नोटिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जारी किया गया था। नोटिस के जवाब में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार ने प्रतिवादी नं. 1. की ओर से लिखित बयान भी दायर किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से भी लिखित बयान दाखिल किया गया है. भारत संघ, प्रत्यर्थी नं. 2, नोटिस की सेवा के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ है।

(3) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने लिखित बयान में कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रदान की गई अधिकांश कारें 1987 मॉडल की हैं। इन कारों के निरंतर उपयोग के परिणामस्वरूप वे अनुपयोगी हो गए हैं और उन्हें आवश्यक मरम्मत के लिए बार-बार कार्य-दुकान पर भेजना पड़ता है जिससे न्यायाधीशों को बहुत असुविधा होती है। रजिस्ट्रार ने लिखित बयान में कहा है कि कर्मचारियों की कारों को बदलने का मामला जांच और रिपोर्ट के लिए न्यायमूर्ति एस. एस. सोढ़ी, को भेजा गया था। न्यायमूर्ति एस. एस. सोढी, जे. ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। न्यायमूर्ति एस. एस. सोढ़ी द्वारा रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के मंत्रियों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में आगे यह सिफारिश की गई थी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कर्मचारियों की गाड़ियों को 80,000 किलोमीटर के बाद बदला जाना चाहिए, 2/3 वर्ष जो भी पहले हो। इन सिफारिशों को उच्च न्यायालय ने पूर्ण न्यायालय की बैठक में स्वीकार किया था। पूर्ण न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के साथ-साथ चंडीगढ़ प्रशासन को 1 फरवरी, 1991 के पत्र के माध्यम से 18 कर्मचारियों की कारों को बदलने के लिए स्थानांतरित किया गया था। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा एक निंदा बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें तकनीकी और यांत्रिक सदस्य शामिल थे। बोर्ड ने मौके पर इन कारों का निरीक्षण किया और केवल 7 कारों की अपरिपक्व निंदा का सुझाव दिया, भले ही सभी 18 कारें पहले ही 80,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी थीं। प्रत्येक। भारत सरकार के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को कारों के प्रतिस्थापन की मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया गया था। प्रत्येक कार द्वारा कवर किए गए कुल माइलेज और प्रत्येक कार पर किए गए कुल अप-टू-डेट खर्च के बारे में सरकार को पूरी जानकारी दी गई थी। इन कारों के प्रतिस्थापन की प्रत्याशित लागत को विधिवत रूप से भारत सरकार को इसकी मंजूरी देने के लिए 20 अक्टूबर, 1992 के पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अब तक भारत सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। लिखित कथन में यह भी कहा गया है कि पूर्ण न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशें कानून के प्रावधानों की भावना के अनुरूप हैं।

(4) प्रतिवादी नंबर 3 (केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन,) ने लिखित बयान दाखिल किया है।लिखित कथन में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि याचिकाकर्ता के पास वर्तमान याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह न तो एक पीड़ित पक्ष है और न ही एक इच्छुक व्यक्ति है और इसलिए वह इस न्यायालय के असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकता है। प्रारंभिक आपत्ति यह भी उठाई गई है कि वर्तमान याचिका जनहित याचिका में नहीं है। एक प्रारंभिक आपत्ति यह भी उठाई गई है कि पंजाब और हरियाणा राज्यों को भी पक्ष बनाया जाना चाहिए क्योंकि अंततः कारों के प्रतिस्थापन पर होने वाले खर्च को

पंजाब और हरियाणा राज्यों द्वारा भी साझा किया जाना है। लिखित बयान में यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को एक स्टाफ कार प्रदान की गई है और प्रदान की गई कारों का रखरखाव स्टाफ कार नियमों के अनुसार किया जा रहा है। यह स्वीकार किया जाता है कि अधिनियम की धारा 22-बी के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हर महीने एक कर्मचारी गाड़ी और एक सौ पचास लीटर पेट्रोल या प्रति माह पेट्रोल की वास्तविक खपत, जो भी कम हो, का हकदार है। लिखित बयान में कहा गया है कि आम तौर पर निंदा के लिए मंजूरी तब दी जाती है जब किसी कार ने 8 साल या 1,50,000 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली हो, जो भी बाद में पहुंचे। हालांकि, भारत सरकार के उच्च न्यायालय के अनुरोध पर नियमों के नियम 43 (11) के तहत पूर्व-परिपक्व निंदा के लिए मंजूरी मांगी गई थी, जिसका इंतजार है।

(5) रिट याचिका में किए गए कथनों पर विचार करते हुए, वर्तमान याचिका स्पष्ट रूप से मामले में जनता में रुचि रखती है। वे उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं। उन्होंने जनहित याचिका में वर्तमान रिट याचिका दायर की है। हमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में कोई बल नहीं मिलता है और इसलिए हम इसे बनाए रखने में असमर्थ हैं।

(6) हम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के इस तर्क में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि पंजाब और हरियाणा राज्यों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्टाफ कार प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। खर्च को साझा करने का सवाल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक आंतरिक व्यवस्था है। मामले के इस दृष्टिकोण में, पंजाब और हरियाणा राज्यों को वर्तमान रिट याचिका में पक्षकारों के रूप में जोड़ना आवश्यक नहीं है,

(7) केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने प्रारंभिक आपत्ति जताई है कि याचिकाकर्ता जो एक अधिवक्ता है, उसके पास वर्तमान याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिका केवल उस व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है जो व्यक्तिगत रूप से मामले में रुचि रखता है। यह सच है कि लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम के अनुसार केवल वही व्यक्ति जिसका कानूनी अधिकार प्रभावित है, आवश्यक राहत देने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का हकदार है। लेकिन आधुनिक समय में जनहित याचिका की अवधारणा विकसित हुई है जो एक जन उत्साही व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय का रुख करने का अधिकार देती है जो अपने पद या पद के कारण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पसंद नहीं करेगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक वकील द्वारा याचिका की रखरखाव के संबंध में प्रश्न की जांच करते हुए, न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती, , न्ययमूर्ति ए. सी. गुप्ता, न्यायमूर्ति जे. एस. मुर्तजा फजल अली न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई, आर. एस. पाठक, न्यायमूर्ति और ई. एस. वेंतरमैया, न्यायमूर्ति एस. गुप्ता और अन्य बनाम भारत के राष्ट्रपति और अन्य (ए आई आर. 1982 एस.सी. 149.) फैसले के पैरा 25 में इस प्रकार कहा गयाः -

याचिकाकर्ताओं के वकीलों के रूप में परिपत्र पत्र की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए पर्याप्त रुचि थी और इसलिए, वे एक जनहित याचिका के रूप में रिट याचिका दायर करने के हकदार थे। उन्हें स्पष्ट रूप से एक व्यस्त व्यक्ति की तुलना में गहरी चिंता थी और उन्हें द्वार पर नहीं बताया जा सकता था।

न्यायाधीश वी. डी. तुलजापुरकर ने अपने सहमति वाले निर्णय में निर्णय के पैरा 609 में इस प्रकार टिप्पणी कीः-"वकालत करने वाले वकील, जो न्यायाधीशों द्वारा किए गए न्याय प्रशासन के कार्य में भागीदारों से कम नहीं हैं, वे वादियों को निष्पक्ष और निडर न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक निर्भीक और स्वतंत्र न्यायपालिका के रखरखाव में अत्यंत रुचि रखते हैं। इसलिए, विधि मंत्री के परिपत्र की संवैधानिकता और उच्च न्यायालय के वर्तमान अतिरिक्त न्यायाधीशों को अल्पकालिक विस्तार की मंजूरी को चुनौती देने में, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों, या तो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में या लॉयर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों का न केवल रिट याचिकाओं के विषय में पर्याप्त हित है, बल्कि उनका अपना विशेष हित है और उन्हें गेट पर नहीं बताया जा सकता है और उनके कहने पर याचिकाएं स्पष्ट रूप से विचारणीय हैं।

(8) उच्चतम न्यायालय द्वारा लोकस स्टैंडी के संबंध में विधि के उपर्युक्त उच्चारण को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता जो इस न्यायालय का अधिवक्ता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन वर्तमान याचिका दायर करने का हकदार है। अतः प्रारंभिक आपत्ति में कोई बल नहीं है।

(9) श्री एम. एल. पुरी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता ने दृढ़ता से तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में परिवहन सुविधाओं के हकदार हैं। अधिनियम की धारा 22-बी के प्रावधान इस प्रकार हैं; "22-बी। -प्रत्येक न्यायाधीश को हर महीने एक कर्मचारी गाड़ी और एक सौ पचास लीटर पेट्रोल या प्रति माह पेट्रोल की वास्तविक खपत, जो भी कम हो, का अधिकार होगा।

उक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हर महीने स्टॉल कार और एक सौ पचास लीटर पेट्रोल या हर महीने पेट्रोल की वास्तविक खपत, जो भी कम हो, के हकदार हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 22-बी न्यायाधीश को परिवहन सुविधा का दावा करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करती है और एक कर्मचारी कार का हकदार है। अधिनियम की धारा 22-बी न्यायाधीशों को स्टाफ कार प्रदान करने के लिए राज्य पर एक वैधानिक दायित्व डालती है। इस सुविधा में यह आवश्यकता निहित है कि उपयोग के लिए आवंटित कार, अपने वर्ग और मरम्मत की स्थिति दोनों में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उच्च स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसी होनी चाहिए जो इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो। दूसरे शब्दों में, यह हमेशा एक अच्छी स्थिति में होना चाहिए, ऐसा वाहन नहीं होना चाहिए जो सामान्य क्षति या अन्य दोष के कारण एक सुरक्षित या विश्वसनीय वाहन नहीं हो, जिसमें यात्रा में टूटने की संभावना हो।

(10) इस प्रावधान का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स का कहना है कि लिआहिगी सी न्यायाधीश के पास स्टाफ कार में यात्रा करने के लिए बुनियादी सुविधा होनी चाहिए। यह सर्वविदित है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को न्यायालयों के निरीक्षण और विशेष पूछताछ करने के उद्देश्य से पंजाब और हरियाणा के जुड़वां राज्यों में दूर स्थित जिला मुख्यालयों का दौरा करना पड़ता है। अधिनियम की इस आपत्ति को पूरा करने के लिए, एक न्यायाधीश के निपटान में रखी गई एक कर्मचारी गाड़ी विश्वसनीय सड़क योग्य और यांत्रिक दोष से मुक्त होनी चाहिए। यह अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा यदि न्यायाधीश के निपटान में रखी गई कर्मचारी गाड़ी पुरानी है और भरोसेमंद नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण के महत्व पर सर्वोच्च न्यायालय ने 'अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ और अन्य में विचार किया था (1992 1 एस.सी.सी. 119.) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः "अलग होने से पहले, हमें अपने आदेश पर पूरे जोर के साथ यह संकेत देना चाहिए कि एक सभ्य समाज के लिए एक प्रबुद्ध स्वतंत्र न्यायपालिका पूरी तरह से अपरिहार्य है। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायपालिका के उचित कामकाज में अधिक रुचि लेनी चाहिए। निरीक्षण आकस्मिक ध्यान देने का विषय नहीं होना चाहिए। अतः प्रत्येक न्यायाधीश को उस संस्था में पर्याप्त रुचि लेनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण में है। हम संयुक्त रूप से यही कह सकते हैं कि लॉर्ड एटकिन्स ने देवी प्रसाद शर्मा बनाम किंग एम्परर में कहा था।और यह बारदाकांत मिश्रा बनाम उड़ीसा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, (1971) 1 एस.सी.सी. में एक संविधान पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया है। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को यह याद रखना चाहिए कि राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों का प्रशासनिक नियंत्रण केवल मुख्य न्यायाधीश में नहीं है, बल्कि उस न्यायालय में निहित है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश करते हैं।

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता है यदि न्यायाधीश के निपटान में रखी गई कर्मचारी गाड़ी भरोसेमंद नहीं है,

(11) यदि सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, कर्मचारियों की गाड़ियों, जो विश्वसनीय और सड़क के योग्य हैं, के निपटान में नहीं रखती है, तो वे निश्चित रूप से अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्यों में विफल होंगे।

(12) स्टाफ कार को कितने माइलेज के बाद बदला जाना चाहिए, इस सवाल को जांच के लिए न्यायमूर्ति एस. एस. सोढ़ी. को भेजा गया था। न्यायमूर्ति एस. एस. सोढ़ी ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के स्टाफ कार नियमों पर विचार करने के बाद देखा कि मंत्रियों को प्रदान की जाने वाली स्टाफ कारों को अलग श्रेणी के रूप में माना जाता है। हरियाणा में मंत्री की देखभाल 2-3 साल और 100000 किलोमीटर के बाद बदली जाती है। जबकि पंजाब में 80000 किलोमीटर के बाद गाड़ी बदल दी जाती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वरीयता देने के क्रम में राज्य सरकार के मंत्रियों के बराबर माना जाता है

और इस स्थिति और गरिमा को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्यायाधीशों के कर्मचारियों की गाड़ियां हमेशा अच्छी कार्य-क्रम में हों, इसलिए यह उपयुक्त है कि उनके साथ दोनों राज्यों के मंत्रियों के समान व्यवहार किया जाए। यह सिफारिश की गई थी कि पंजाब की तरह, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्टाफ कारों को 80000 किलोमीटर के बाद बदल दिया जाए, या तीन साल के बाद, जैसा कि मामला हो सकता है।

(13) पूर्ण न्यायालय की बैठक में सभी न्यायाधीशों की बैठक में न्यायमूर्ति एस. एस. सोढ़ी की रिपोर्ट पर विचार किया गया। उच्च न्यायालय ने सरकार से सिफारिश की कि न्यायाधीशों के निपटान में रखे गए कर्मचारियों की गाड़ियों को 80,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बदला जाना चाहिए या तीन साल बाद। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के लिखित बयान के अनुसार, प्रशासन ने उच्च न्यायालय के सुझावों को स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की है। केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(14) नोटिस की सेवा के बावजूद भारत संघ ने कोई लिखित बयान नहीं छिपाया है। उच्च न्यायालय की सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लेने में अत्यधिक देरी स्पष्ट रूप से सरकार पर डाली गई वैधानिक जिम्मेदारी का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य अधिनियम के उद्देश्य या धारा 22-बी को पूरा करना है। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यह प्रदान करना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निपटान में रखी गई कारें अच्छी काम करने की स्थिति में हों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए 80,000 किलोमीटर की दूरी तय की है या तीन साल की हो। उच्च न्यायालय की सिफारिशों को लागू न करने में सरकार की ओर से शायद ही कोई औचित्य हो। ऐसा करने में विफलता स्पष्ट रूप से सरकार पर डाली गई वैधानिक जिम्मेदारी का उल्लंघन है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रजिस्ट्रार (उच्च न्यायालय का जनरल भी संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत जिम्मेदारियों के निर्वहन में उच्च न्यायालय की मदद करता है। जब वह आधिकारिक कार्य के लिए दिल्ली या पंजाब और हरियाणा राज्यों के किसी अन्य हिस्से में जाते हैं तो उन्हें मुख्य न्यायाधीश के साथ जाना पड़ता है। अन्यथा भी रजिस्ट्रार (जनरल) के निपटान में रखी गई कार विश्वसनीय और सड़क के योग्य होनी चाहिए। उसे दी गई गाड़ी भी उचित होनी चाहिए। रजिस्ट्रार (जनरल) को दी गई गाड़ी को भी 80,000 किलोमीटर के बाद बदला जाना चाहिए या पाँच साल बाद। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि रजिस्ट्रार (जनरल) जो उच्च न्यायालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, आमतौर पर पंजाब और हरियाणा के दो सहयोगी राज्यों में से किसी एक के सबसे वरिष्ठ जिला और सत्र न्यायाधीशों में से एक होता है, जो अपनी सेवा शर्तों के साथ-साथ अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में एक कर्मचारी कार का हकदार है।

(15) यह श्री आर. एल. शर्मा, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के जिला अटार्नी द्वारा तर्क दिया गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारी कार नियम एक वाहन को 1,50,000 कि. मी. दौड़ने के बाद दंडित किया जाता है ,उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिनियम की धारा 22-बी के तहत स्टाफ कारों के हकदार हैं। कर्मचारियों की कारें भरोसेमंद और सड़क के लायक होनी चाहिए। कारों की निंदा के संबंध में सरकार का सामान्य नियम नहीं हो सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू किया जाता है क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिनियम की धारा 22-ख में किए गए विशेष प्रावधान को देखते हुए एक अलग श्रेणी में आते हैं। यही कारण था कि न्यायमूर्ति एस. एस. सोधी द्वारा मामले की गहन जांच के बाद, पुल कोर्ट की बैठक में न्यायाधीशों ने 80,000 किलोमीटर के बाद कारों को बदलने के लिए टंडिया सरकार को सिफारिश करने का निर्णय लिया।

(16) यह उल्लेख किया जा सकता है कि कानून द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को पूरा करने के लिए, सरकार को अधिनियम की धारा 24 के तहत नियम बनाने की शक्ति है। सरकार द्वारा बनाए गए वैधानिक नियमों के अभाव में सरकार को उच्च न्यायालय की सिफारिशों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लेने में अत्यधिक देरी, स्पष्ट रूप से न्यायाधीशों को स्टाफ कार प्रदान करने के लिए वैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफलता का गठन करती है।

(17) उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उत्तरदाता न्यायाधीशों को स्टाफ कार प्रदान करने के लिए बाध्य हैं और कार के 80,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उन्हें बदला जाना चाहिए या पाँच साल पुरानी है। उच्च न्यायालय के पंजीयक द्वारा दायर लिखित बयान के अनुसार न्यायाधीशों को प्रदान की गई बड़ी संख्या में कारें पहले ही 80,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी हैं। या पाँच साल पुरानी है। गाड़ियों को महंगी मरम्मत की आवश्यकता होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निपटान में रखी गई गाड़ियों को बदलने में देरी करने का कोई औचित्य नहीं है, जो पहले ही 80,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। या पाँच साल पुरानी है।

(18) याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका में यह भी दावा किया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उचित सुरक्षा का अधिकार है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रतिदिन आपराधिक मामलों का फैसला करते हैं जिनमें से कुछ कट्टर अपराधियों के होते हैं। वे उचित सुरक्षा के बिना अपने न्यायिक कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते। न्यायाधीशों की सुरक्षा की पर्याप्तता का निर्णय प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। यह माना जा सकता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पूरी तरह से पता है कि न्यायाधीशों को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सरकार को मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए। हालाँकि, हम अर्थव्यवस्था के एक उपाय के रूप में मानते हैं कि जिन कारों ने 80,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। या पाँच साल पुरानी है। जो भी पहले हो, उन्हें बदला जाना चाहिए।

(19)उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका अनुमत है और प्रत्यर्थी सं 2 और 3 को निर्देश देते हुए आदेश का एक रिट जारी किया जाता है को तत्काल सात कारों को खरीदने और बदलने के लिए, जिनमें से एक रजिस्ट्रार सीजी के लिए है) जिसके लिए एक संदर्भ पहले ही जारी किया जा चुका है। यह खरीद और प्रतिस्थापन 30 तारीख को या उससे पहले पूरा हो जाना चाहिए । ऐसा न करने पर प्रतिवादी नंबर 1 के लिए खरीदारी करना और कारों की खरीद कीमत डेबिट करना अनिवार्य होगा। आगे निर्देश दिया कि प्रतिवादी उन कारों को बिना किसी देरी के बदल देगा जो पहले ही 80,000 किलोमीटर चल चुकी हैं या पांच साल से अधिक पुरानी हैं, जो भी पहले हो। यह प्रतिस्थापन भी 1 मई, 1993 तक किया जाना चाहिए।

(20) विशेष परिस्थितियों को देखते हुए; शूल्क के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह

अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा

सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण

प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्या न्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश जिंदल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा